

RAJYA SABHA

Monday, the 13th August, 1984/
22 Sravana, 1906 (Saka)

The House met at eleven of the
Clock, Mr. Chairman in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Jl. [The questioner (Shri V. Gosamy) was absent. For answer vide -ol. 30—32 infra].

News report on IDPL workers, demand for New Drug Policy

*302. SHRI CHATURANAN MISHRA: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state;

(a) whether Government's attention has been drawn to the news report captioned 'IDPL workers demand New Drug Policy' which appeared in "New Age" weekly dated the 5th August, 1984; and

(b) if so, what are the details in this regard and what is Government's reaction to the various demands raised at the Conference of the All India IDPL Employees' Federation?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI VASANT SATHE): (a) and (b) Government have seen the news report captioned "IDPL workers demand new drug Policy" which appeared in the "New Age" Weekly, dated 5th August, 1984. The All India IDPL Employees Federation had not submitted any demands to the Government.

श्री चतुरानन मिश्र : सभापति महोदय, दवा उद्योग की हालत अत्यन्त ही खराब है। जहाँ तक जनता का प्रश्न है, जखरी से जखरी दवा भी बाजार में नहीं पा रही है और जहाँ तक पब्लिक सेक्टर की कर्माडिंग हाइट में पहुँचाने की बात है, दवा एक ऐसा उद्योग है, जहाँ हम अपने जखरी का देश में जो उत्पादन करते हैं उसका 25 परसेन्ट भी राजकीय क्षेत्र में नहीं पैदा कर पा रहे हैं। इसलिये हमें विदेशों से

दवाइयाँ मँगानी पड़ती हैं। हमारे देश में जो कम्पनियाँ हैं वे ज्यादातर फारन मल्टीनेशनल कम्पनियाँ या उनकी सब-सोडियरी हैं जो 65 परसेन्ट उत्पादन करती हैं। फार्मूलेशन्स में तो और भी स्थिति खराब है। पब्लिक सेक्टर केवल मात्र 6 से 7 परसेन्ट फार्मूलेशन्स कर रहा है। बाकी सारा काम विदेशी कम्पनियाँ, मल्टीनेशनल कम्पनियाँ या भारतीय स्वामिनी कर रही हैं। विदेशों से सब-स्टैंडर्ड दवाएँ भी आती हैं। इस समय देश में स्पुर्चिस ड्रग्स इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि हम लोग दवा खाते हैं या जहर खाते हैं, कहना बहुत मुश्किल हो गया है। पता नहीं हम लोग ड्रग्स के नाम पर क्या खा रहे हैं? ऐसी स्थिति में मैं सरकार से यह पुछना चाहता हूँ कि दवा के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिये और राजकीय क्षेत्र को कर्माडिंग हाइट में पहुँचाने के लिये सरकार क्या कदम उठाने जा रही है और राजकीय क्षेत्र में जो भीतर घात हो रहा है उसे रोकने के लिये सरकार क्या करने जा रही है?

श्री वसन्त साठे : सभापति जी, पहले तो मैं एक बात साफ कर दूँ कि पब्लिक सेक्टर और इंडियन सेक्टर में जहाँ तक ड्रग्स के शेयर का सवाल है, अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि परदेशी कम्पनियाँ बहुत ज्यादा कम से कम 70 परसेन्ट या 75 परसेन्ट अभी भी प्रोडक्शन कर रही हैं, यह बात सही नहीं है। असल में परसेन्टेज के मुताबिक देखा जाय तो 1982-83 में पब्लिक सेक्टर का प्रोडक्शन 20.6 परसेन्ट, इंडियन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का प्रोडक्शन है, बल्क ड्रग्स की बात मैं कर रहा हूँ वह 37.2 परसेन्ट परदेशी या तो विदेशी कम्पनियों का 22.2 परसेन्ट और स्माल स्केल सेक्टर का 27.5 परसेन्ट है। यह

स्थिति बल्क ड्रग्स में है। फारमूलेशन्स में पब्लिक सेक्टर का आँकड़ा सन् 1984-85 में प्रोडक्शन के मुताबिक 13.5 परसेन्ट है और इंडियन आर्गनाइज्ड सेक्टर का 37.1 परसेन्ट है। फोरा कम्पनियों का विदेशी कम्पनियों का 29 परसेन्ट है और स्माल स्केल सेक्टर का 20 परसेन्ट है। इस तरह से आप देखेंगे कि परदेशी कम्पनियों का हिस्सा बल्क और फारमूलेशन्स में अर्थात् दोनों में 30 परसेन्ट से कम हो गया है और हिन्दुस्तानी सेक्टर जिसमें पब्लिक सेक्टर में पहल हुई है उसको वजह से यह सारी आज हिन्दुस्तानी सेक्टर में, 70 परसेन्ट दबाएँ बल्क और फारमूलेशन्स में बन रही हैं। तो इतनी तो प्रगति हुई है। यह मैंने बल्क सेक्टर का बताया। एक बात ध्यान में रखने की है कि पब्लिक सेक्टर ने जो पहल की उसमें जखुरा दवायें बनाना, एन्टी-बायोटिक, सेप्टिक, वाइ-लाजिकल यह बनाना हमने शुरू किया लेकिन प्राइवेट कम्पनियों जैसा तत्त्वको हम नहीं कर पाये। कमशिवल बंग पर जैसा हो सकता था वैसा नहीं हो पाया यह हालत है। यह तो मैंने माना है कि यह सही बात है कि हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिटों को दवाओं के क्षेत्र में जिस तरह से कामयाब होना चाहिये था, जिस तरह से कुशलता से उन्हें काम करना चाहिये था वह नहीं कर पाये। हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करीब 50 प्रतिशत हुई है, यह दुखद बात है और हमें उसमें काफी सुधार करना पड़ेगा। कुछ सुधार पिछले दो सालों में हुआ है 27 करोड़ लाख 80-81 में आई०डो०पी० एल० का था, अब वह लाख दो सालों में 14 करोड़ पर आ गया है। 14 करोड़ आप कहेंगे कि लाख तो है। यह मैंने खुद माना दुख के साथ माना है। लेकिन एक बात की दाद देनी पड़ेगी कि दो साल में 50 प्रतिशत से

ज्यादा घाटा कम कर दिया और हम उम्मीद करते हैं कि धीरे-धीरे मामला ठीक हो जायेगा, इतना ही मैं कह सकता हूँ।

श्री सभापति : उन्होंने एक सवाल रखा है कि दवा मिलती है या जहर।

श्री बसन्त साठे : आई०डो०पी०एल० और पब्लिक सेक्टर को तर्फ से मैं दावे से कह सकता हूँ कि कोई जहर नहीं जाता। स्माल स्केल सेक्टर में और दूसरे सेक्टर में यह स्पूग्निश ड्रग्स का मामला है यह मैं मानता हूँ। क्योंकि देश में करीबन 10 हजार यूनिट हैं जो यह काम करती हैं। अमेरिका जैसे बड़े देश में 5 सौ यूनिट हैं और हमारे यहां 10 हजार हैं तो इनका कंट्रोल कौन करे। दूसरा, यह कंट्रोल हमारी मिनिस्ट्री में नहीं आता, यह हेल्थ मिनिस्ट्री में आता है। फिर भी स्पूग्निश ड्रग्स का जो बात है हमें इसको रोकना चाहिये यह बात मैं मानता हूँ।

श्री विश्वजित पृथ्वीजित सिंह : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने देखा होगा कि अब हम दवायें खरीदते हैं तो उन पर लिखा होता है कि यह जहर है।

श्री चतुरानन मिश्र : सभापति महोदय अभी मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया कि पब्लिक सेक्टर घाटे में चलता है। इसका एक कारण तो यह है कि राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार कुल जितनी दवायें खरीदते हैं, पब्लिक सेक्टर से, वह 10 प्रतिशत से भी कम है। अगर आप अपनी दवाइयों को नहीं खरीदेंगे तो कौन आपको बचायेगा। आज हालत ऐसी है कि यहां न पब्लिक सेक्टर सक्सीड कर रहा है और न प्राइवेट

सेक्टर। 420 सेक्टर जो हैं, स्पूरियस ड्रग का वही सक्साइ कर रहा है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि भाटिया कमेटी ने सुझाव दिया था और वर्ल्ड हेल्थ आर्गनाइजेशन ने भी सुझाव दिया था कि दवाओं को फार्मूलेशन के लिये छोटी छोटी कम्पनियों को इसकी इजाजत नहीं देनी चाहिये। लेकिन ये इजाजत दे रहे हैं। इसलिये मेरा प्रश्न है कि स्पूरियस ड्रग को रोकने के लिये क्या क्वालिटी कंट्रोल का भार आई०डी०पी०एन० को सारना देगे ताकि जो 5 सौ या 5 हजार, जितनी भी कम्पनियाँ हैं उनकी दवाओं का क्वालिटी कंट्रोल ह्वारा आई०डी०पी०एन० करे ताकि देश को स्पूरियस ड्रग नहीं बल्कि उचित ड्रग मिले? तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ऐसा करेगी?

श्री वसन्त साठे : सभासद जी, जैसा मैंने शुरू में कहा कि इन प्रोडक्शन और ड्रग कंट्रोल स्टेट में इन अथॉरिटी इसको इजाजत देता है, यह पालिसी है। सदा या पार्लियामेंट यदि यह कहे कि इसका सेंटर को अधिकार होता चाहिए, इन प्रोडक्शन और उसके डिस्ट्रिब्यूशन और उसको कंट्रोल करता यह पालिसी की बात है।

श्री चतुरानन मिश्र : क्वालिटी कंट्रोल?

श्री वसन्त साठे : प्रोडक्शन में क्वालिटी कंट्रोल होगा नहीं तो कहा होगा। तो इसलिए यदि यह अधिकार मिलता है तो यह पालिसी की बात है। हमने अभी नेशनल ड्रग कौंसिल बनाई है। उनकी रिपोर्ट में हमें क्या सलाह मिलती है यह देखेंगे। लेकिन व्यवहार में आज राज्यों के अधिकारों पर अतिक्रमण करना

और सारे प्रोडक्शन को उसकी क्वालिटी का क्या डिस्ट्रिब्यूशन को कंट्रोल करना आज आई०डी०पी०एन० के लिए संभव नहीं है।

SHRI VISHVAJIT PRITHVIJIT SINGH : Mr. Chairman, the Hon'ble Minister has given us certain figures of percentage rise of bulk drug production and formulation by the public sector, by the Indian sector and by the foreign sector. What is the actual ratio of these with regard to Schedule I drugs under the present drug policy because these are essential drugs for various kinds of endemic diseases and for life support. What is their present share of production by public sector, by the Indian sector and by foreign sector?

SHRI VASANT SATHE : I can give only some instances. The bulk drugs where the public sector share is hundred per cent in what is known as Schedule I are Sulphanamids, Sulphanamide-dim, and Sulphanilamide. These are sulpha drugs. Then among Vitamin drugs, there are vitamin B-2, Folic Acid, Vitamin B-6 and there is anti-gangrene syrup. The bulk drugs where the public sector share is between 50 and 100 per cent are streptomycin, Tetracycline....

MR. CHAIRMAN : What follows out of it?

SHRI VASANT SATHE : The thrust of the Hon'ble Member's question was what is the percentage which public sector is producing in regard to bulk drugs in Schedule I. I would tell him that public sector is playing a very important and major role in the production of these drugs.

DR. JOSEPH LEON D'SOUZA : Mr. Chairman, the Hon'ble Minister has admitted that the working of the IDPL is far from what can be considered satisfactory. The Hon'ble Minister has also from time to time given data in answer to Starred and Unstarred Questions in regard to the targets fixed in terms of production

value and the actual production between years ranging from 1980 to 1983.

It is alarming to note from this data that in the last three years there has been a steady increase in the loss incurred by this public sector and it has run into crores of rupees. The production value has persistently and consistently come down. It is pathetic to note that the Government has shown scant concern regarding this untenable situation. It is true that on all occasions the Hon'ble Minister has tried to explain this off by assigning reasons such as outmoded installation of machinery, outdated technology and defective marketing system. All accepted. But I have concrete > vidence with me at my disposal to prove that a particular plant was set up in IDPL with a technology which was purchased at an exorbitant price from a foreign country. From the inception or starting of this plant, precious little was produced worth mentioning. I am referring to Erythromycine which was sought to be produced by IDPL for which Rs. 33 lakhs were paid for the technical know-how and Rs. 1.75 crores were spent in setting up the plant and machinery. Roughly it comes to Rs. 2 crores. It was supposed to have an installed production capacity of 35 tonnes. But, Sir, it never produced more than 200 to 300 kgs. per year. And, in four years, when it had to produce 130 tonnes, it has produced only one tonne, Sir. This is the authentic data given by the honourable Minister in answer to an Unstarred Question which I am prepared to table in this House. Now, this works out to a ratio of 1.85 tonnes of production in four years. This certainly merits going down in the Guinness Book of World Records because no country has achieved anything like this. Now, Sir, it is right to presume that the technology purchased was outmoded. But certainly the Members of Parliament have a right to ask, if this technology that was bought and sought to be employed could not be used or could not be made use of, why an amount of Rs. 33 lakhs

was paid, who gave the 'O.K.' for this technology and where exactly was the mistake. This is what I want to know. I cannot blame the Finance Ministry because the Finance Ministry has nothing to do with this. Only on the certification given by the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the Finance Ministry naturally said, "O.K.". But what happened to the two crores of rupees that we have spent? I am on this vital question now and every Member of Parliament would like to know what happened to the money that was spent and also to our public? Therefore, Sir, I do hope that the honourable Minister will appreciate the fact that the losses incurred are almost coming to match your investments which is very serious. Therefore, will the honourable Minister assure this House that a Committee would be constituted, a Committee consisting of Members of both Houses of Parliament, to inquire into this matter and to see where the defects are, what can be done about them, how we can revive this plant and how we can retrieve our losses? This is in the national interest and this cannot be just brushed aside.

SHRI VASANT SATHE: Thank you for your elucidation and lecture.

DR. JOSEPH LEON D'SOUZA: Elucidation of facts.

SHRI VASANT SATHE: As far as the facts are concerned, he began by saying that the IDPL's production has been going down progressively. Sir, production in terms of value, in 1979-80, was 6,462—in terms of lakhs of rupees—and in, 1983-84, it has doubled and gone to 12,155. I have already stated that we have been incurring losses. But I have also stated that the loss has come down within two years from Rs. 27 crores to Rs. 14 crores. So, on both sides, we are producing more and we are also selling and reducing our losses which I have said. But facts are facts.

MR. CHAIAMAN: What about erythromycin?

DR. JOSEPH LEON D'SOUZA: What about formulations? (*Interruptions*). What about the bulk drugs? It is only zero. What about erythromycin? Have you produced more than one tonne in four years?

SHRI VASANT SATHE: Just hear me.

DR. JOSEPH LEON D'SOUZA: Is not the factory lying idle?. It is lying idle and I have seen it. (*Interruptions*). It breaks my heart to see that two crores of our country's money has been sunk in it. (*Interruptions*).

SHRI VASANT SATHE: Sir, bulk drug production in 1979-80 was 2,233; it increased to 2,948 in 1983-84. So, this is on bulk drugs. Erythromycin is the case where in the case of the technology which we had bought we found that producing it from the basic stage was not commercially viable and, therefore, the production was given up. If you give up the production of a particular drug, how can you complain that there has been no production at all?

DR. JOSEPH LEON D'SOUZA: But who certified the technology? (*Interruptions*). That is my question.

SHRI VASANT SATHE: We do not have....

DR. JOSEPH LEON D'SOUZA: I want to know what were the conditions laid down? (*Interruptions*) What were the conditions laid down?

SHRI VASANT SATHE: Expert committees are there... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: He is another expert.

DR. JOSEPH LEON D'SOUZA: When you have already spent....

SHRI VASANT SATHE: Are you going to allow this cross-examination? (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: I think you better dry up, Dr. D'Souza. I think the main question, which is very important, is that you spent a large sum of money on acquiring the know-how and that knowhow did not turn out to be successful and you produced almost nothing of Erythromycin. You explained it by saying that you did not find it useful.

DR. JOSEPH LEON D'SOUZA: Sir, there is a thing known as accountability. Government must account for the sanity to spend Rs. 33 lacs for the purchase of a Technical know-how which was of non-commercial use.

SHRI VASANT SATHE: It so happened that as far as this technology is concerned for producing Erythromycin, its technology was proven, but when we started producing it, it was seen that commercially it was not viable to produce it from the basic stage. Now, what do we do? Finally it was given up. Sir, we have to go by the technical experts. I am not myself an expert. Dr. D'Souza is an expert, (*Interruptions*)

DR. JOSEPH LEON D'SOUZA: He is making a personal allegation. (*Interruptions*)

SHRI VASANT SATHE: I have not made an allegation. I have said that he is an expert. It is not an allegation. If he does not like it, I withdraw my statement. You are not an expert. (*Interruptions*).

SHRI KALYAN ROY: I think we should have half-an-hour discussion.

MR. CHAIRMAN: Mr. Chatterjee.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: My question is on a different keel altogether. He has given figures of public sector output, foreign sector output, **FERA** companies output, then the private organised sector and small

scale sectors outputs^ The problem is that the 'small scale sector, the units of small-scale sector, are defined in terms of the scale of operation. It is in the pharmaceutical and drugs sector that foreign capital is working. There is a publication of the Indian Institute of Public Administration about the small scale industry. And the definition of the FERA company is also interesting. Now, supposing there is a foreign fund to the extent of 20 per cent of the capital, it is not a FERA company at all. Can the Minister enlighten on this? As Dr. D'Souza has indicated, there are many failures as the hon. Minister has also admitted. These failures are matched by these foreign-owned companies which are not included within the FERA group but which are in other private sector organised units as well as in the small-scale sector. What are the facts with regard to this?

SHRI VASANT SATHE: Sir, as far as the FERA definition is concerned, it is a definition given by the Finance Ministry and by the economic Ministries. We go by that definition. That is why, those which are below 40 per cent in equity are considered one category. Now, as far as the small-scale sector is concerned, to our knowledge, the FERA companies are not engaged in the small-scale sector. But if there are any 'henami' companies, we have no direct knowledge if there is such involvement. That is true about the Indian Sector, that is true about any large scale sector. Therefore, in regard to the facts which the honourable Member expects from me of foreign involvement in small-scale sector, I am sorry I don't have those figures. If he can furnish some information I will make inquiries.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: If the Minister is willing, I am referring to a particular book, a research product, of the Indian Institute of Public Administration written by Mr. Goyal. He has underlined that it is in the pharmaceutical line that it is particularly evident.

SHRI VASANT SATHE: I will read that book. Thank you.

Demand of Tamil Nadu Chief Minister for supply of Power Generator at Kalpakkam Atomic Power Station to Tamil Nadu

303. SHRI SURAJ PRASAD: t

SHRI INDRADEEP SINHA:

Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Chief Minister of Tamil Nadu has demanded that the entire power generated at Kalpakkam atomic power station be made available to Tamil Nadu; and

(b) if so, what are the details in this regard and what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI ARIF MOHD. KHAN): (a) and (b) The Chief Minister of Tamil Nadu has requested that the entire power from the first unit of the Kalpakkam atomic power station may be allocated to Tamil Nadu. Tamil Nadu has also asked for allocation of 50 per cent power to be generated from the second unit at Kalpakkam.

The present policy of Government, which has gradually evolved over the last few years, is to treat the Central sector power stations, including atomic power plants, as regional stations intended for supplementing the power requirements of the different States in each region.

श्री सूरज प्रसाद : माननीय सभापति महोदय मैं सरकार से यह ज्ञान चाहूंगा कि इस पावर प्लांट से अभी कितनी बिजली पैदा होती है और इसमें बिजली पैदा करने का कितना लक्ष्य है और किस अनुपात में विभिन्न राज्यों में बिजली का वितरण करने के संबंध में सरकार की नीति है ?

†The Question was actually asked on the floor of the House by Shri Suraj Prasad.